



कोविड-19 के दौरान सिर्फ 18 दिनों के लिए हुई महाराष्ट्र राज्य विधानसभा की बैठक, लॉकडाउन के बाद केवल चार दिन

26 July 2022



मुंबई। 2020 में, 19 विधानसभाओं में, जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध थे, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा सत्रों की अवधि के मामले में 10वें स्थान पर थी, जबकि कर्नाटक और राजस्थान क्रमशः 31 और 29 दिनों के साथ उच्चतम क्रम पर थे।

मुंबई। प्रजा फाउंडेशन ने मंगलवार, 26 जुलाई, 2022 को मुंबई के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जारी

किया। यह संवाददाता सम्मेलन विधायकों के संवैधानिक और विधायी कर्तव्यों के आधार पर रिपोर्ट कार्ड के निष्कर्षों और विधायकों की क्रमांकन / प्रदर्शन को साझा करने के लिए था। कोविड-19 के दौरान, यह देखा गया कि सत्रों की अवधि में गिरावट आई। इस लिए प्रजा ने वार्षिक रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित न करके, इस साल शीतकालीन सत्र 2019 से मानसून सत्र 2021 तक की अवधि के लिए 'समेकित दो साल का रिपोर्ट कार्ड' प्रकाशित करने का निर्णय किया।

“कोविड-19 ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित थे और इनको राज्य विधायी से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को अधिक बैठक करने की आवश्यकता थी ताकि समावेशी निर्णय लिए जा सकें। हालांकि, 14 वीं विधानसभा में प्रति सत्र औसतन अवधि केवल 6 दिन था, जबकि 12 वीं विधानसभा में औसतन 15 दिन था। इसके अलावा, 2020 में, 19 विधानसभाओं में से, जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध थे, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा सत्रों की अवधि के मामले में 10वें स्थान पर थी जबकि कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्य 2020 में क्रमशः 31 और 29 दिनों के साथ उच्चतम क्रम पर थे”, प्रजा फाउंडेशन के सी.ई.ओ. मिलिंद म्हस्के ने कहा। म्हस्के ने कहा, “कोविड-19 के दौरान सत्रों की कम अवधि के अलावा, विधायकों को मुंबई के लिए समावेश निर्णय लेने के लिए विधानसभा में अधिकतम मुद्दों को उठाने की आवश्यकता थी। हालांकि विधायकों के विचार विमर्श, 12 वीं विधानसभा के पहले वर्ष (शीतकालीन 2009 – मानसून 2010) में 7,955 में 74% गिरकर, 14 वीं विधानसभा के पहले वर्ष (शीतकालीन 2019 – मानसून 2020) में 2,056 हो गई।”



“पिछले अवधि की प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चलता है, कि जैसे-जैसे सत्र आगे बढ़ता गया, सत्रों की अवधि में गिरावट आई है। उदाहरण के लिए, 13वीं विधानसभा में – अवधि पहले वर्ष (शीतकालीन 2014 से मानसून 2015) में 50 दिनों से 52% घटकर अंतिम वर्ष (शीतकालीन 2018 से मानसून 2019) में 24 दिनों तक आ गई। इसी तरह विधायकों की उपस्थिति पहले साल के 95% से घटकर अंतिम साल में 87% हो गई। इस प्रवृत्ति ने नागरिकों के मुद्दों पर पूछे गए समग्र प्रश्नों को प्रभावित किया, जो पहले वर्ष में 4,402 से 23% घटकर कार्यकाल के अंतिम वर्ष में 3,373 हो गया,” प्रजा फाउंडेशन के संवाद कार्यक्रम के प्रमुख योगेश मिश्रा ने कहा।

मिश्रा ने कहा, “शीतकालीन 2019 से मानसून 2021 में मुंबई के विधायकों के समग्र कार्यक्षमता पर नज़र डालें, तो 31 में से 13 विधायकों को 50% या कम का समग्र अंक मिला, जबकि केवल 1 विधायक ने 80% या अधिक अंक हासिल किया है। दूसरी ओर, 31 में से 30 विधायकों को उपस्थिति प्राचल में 80% और अधिक की रैंक प्राप्त हुई। हालांकि, केवल 11 विधायकों ने शीतकालीन 2019 से मानसून 2021 तक 150 से अधिक सवाल उठाए। ‘पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता’ पैरामीटर में, 31 विधायकों में से किसी ने भी 80% या अधिक का अंक हासिल नहीं किया। अतः उच्च उपस्थिति स्कोर के बावजूद, यह विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों की संख्या और गुणवत्ता पर प्रतिबिंबित नहीं करता है,।”

हाल ही में एक समाचार लेख (18 जून, 2022) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा, कि चुनावी प्रक्रिया में प्रतिभागियों की ईमानदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है। प्रजा भी अपने रिपोर्ट कार्ड में निर्वाचित प्रतिनिधि के आपराधिक रेकॉर्ड का विश्लेषण करता है। 13 वीं विधानसभा के पहले दो वर्षों में 15 विधायकों से 27% की वृद्धि हुई और 14वीं विधानसभा की समान अवधि में 19 विधायक हो गए , जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है।

म्हस्के ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि, “इस महीने, महाराष्ट्र सरकार ने एक नए मुख्यमंत्री के साथ नेतृत्व में बदलाव देखा। यह विधायी और कार्यकारी पक्ष के प्रभावी शासन और सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का अवसर लाता है। यह उचित नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी तंत्र के साथ-साथ लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए एक परिणाम-आधारित बजट के निर्माण के साथ किया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि मुंबई महामारी से उबर रहा है, आयोजित सत्रों की अवधि में वृद्धि का समय है। विधायकों को नीतियां बनाने के लिए प्रभावी विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत करने और मुंबई में सभी के लिए पर्याप्त आवास प्रदान करने के लिए। यह राज्य में नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए नीतियों और कानून में सुधार सुनिश्चित कर सकता है और महाराष्ट्र के समग्र शासन को मजबूत कर सकता है”।

प्रजा फाउंडेशन सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए पिछले दो दशकों से काम कर रही है। नागरिक मुद्दों पर आँकड़ों का अध्ययन करके और नागरिकों, मीडिया और सरकार और प्रशासनिक निकायों को इसकी जानकारी प्रसारित करके, प्रजा जनप्रतिनिधियों के साथ भी काम करती है।

Link: <https://surabhisaloni.co.in/archives/116593.html>